STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI KAMALUDDIN AHMED): (a) No, Sir. The requirement of such a notification would arise only after zone units are approved and begin to effect imports;

(b) Yes, Sir.

(c) Issue of Customs and Central Excise Notifications for declaring Visakhapatnam Export Processing Zone as a bonded area has been taken up with the Department of Revenue and the same is expected to issue shortly.

इराक सरकार पर बकाया राशियां

3161. **श्रीमती सुषमा स्वराज :**
श्री राम जेठमलानी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश की विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी संस्थाओं की बड़ी-बड़ी राशियां इराक सरकार पर बकाया हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ गठित ओवरसीज कंस्ट्रक्शन काउंसिल आफ इंडिया की गत माहों में बैठक हुई थी ;

(ग) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि लगभग 2100 करोड़ रुपए की बड़ी धनराशि को वसूल करने में सरकार की मदद की आवश्यकता अनुभव की जा रही है ; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री और वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ग) जी हां ;

(घ) भारत सरकार तथा इराक के बीच आस्थगित भुगतान प्रबंधों के तहत इराक से तेल की खरीद के बदले तेल भुगतानों के कुछ अंश का समायोजन उन राशि के प्रति कर दिया गया था जिसका भुगतान उन परियोजना निर्यातकों को किया जाना था जिन्होंने इराक में परियोजनाएं निष्पादित की थीं । खाड़ी संकट आरंभ होने तथा संयुक्त राष्ट्र व्यापार रोक लगाए जाने से कच्चे तेल का आयात नहीं किया जा सका और इसलिए अगस्त, 1990 से आस्थगित भुगतान प्रबंध के तहत कोई भुगतान वसूल नहीं किये जा सके । सरकार ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद समिति के साथ जनवरी, 1991 में इस संभावना के बारे में मामला उठाया था कि इराक भारत को भारतीय निर्माण कंपनियों को दी जाने वाली बकाया राशि के बदले में तेल उपलब्ध कराए । तथापि, उनकी प्रतिक्रिया अनुकूल नहीं रही । सरकार इराक पर से संयुक्त राष्ट्र व्यापार रोक उठाए जाने के बाद इराक भुगतान प्राप्त करने के लिए प्रबंध की व्यवस्था कर सकती है ।

Associate Chambers of Commerce and Industry Statement on Export Target

3162. SHRI KAMAL MORARKA : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the reported statements of Associate Chambers of Commerce and Industry stating that India can double its exports by 1995-96 if impediments are removed;

(b) if so, what is Government's reaction thereon; and

(c) what steps are proposed to be taken in this direction?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI KAMALUDDIN AHMED): (a) A paper on 'Doubling Exports' in five Select Focus Product Groups by 1996-97' was circulated as a backgrounder for a Seminar on the subject organised by the Associated Chambers of Commerce and Industry of India in New Delhi on 14th August, 1993.

(b) and (c) Government is always responsive to suggestions that are conducive to growth in exports. Steps are taken whenever necessary to remove the problems brought up by trade and industry.

Export of Cigarettes

3163. DR. YELAMANCHILI SIVAJI : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether it is a fact U.S. cigarette manufacturers enhanced their exports to Japan from 3 billion pieces to 60 billion pieces between 1987 and 1992;

(b) whether it is also a fact that Indian premium brands of cigarettes are more price competitive as compared to their American counterparts;

(c) if so, what are our cigarette exports to Japan for the last three years;

(d) whether it is a fact that our domestic cigarette manufacturers are not entering Japan and other markets of advanced countries, since their parent

concerns like British-American Tobacco Co. Philips Mills are exporting cigarettes to these countries so as to avoid competition;

(e) what steps are taken to export our cigarettes to the above said countries; and

(f) at what steps are these efforts ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI KAMALUDDIN AHMED) : (a) U.S. cigarette exports to Japan have gone up from 31.95 billion pieces in 1987 to 57.70 billion pieces in 1992.

(b) In quality terms our premium blends of cigarettes are not comparable with American premium blends.

(c) Nil.

(d) No authentic information is available on this aspect.

(e) and (f) Steps taken to boost exports include :—

Sending trade delegation to identified markets of FCV tobacco and products.

Participation in International Exhibitions.

Aggressive publicity in overseas markets.

Pursuing with Governments through Joint Committee meetings etc., to import Indian tobacco and products.

Inviting delegations from tobacco organisations of identified markets to familiarise them with the Indian Tobacco Industry, the quality of Indian tobacco and holding discussions with Indian exporters.

Promoting Export Oriented Units for export of cigarettes and cut tobacco.

Permitting foreign investment in cigarette industry mainly for export of cigarettes and value added products.

Permitting cigarette manufacturers to import various items with a view to enable them to undertake product developments.

भारतीय व्यापार संवर्धन संस्थान में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पद

3164. **श्री मूलचन्द मीणा :**

प्रो० आई० जो० सनदी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय व्यापार संवर्धन संस्थान में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कितने पद रिक्त हैं ;

(ख) उन पदों को भरने के लिये क्या प्रयास किये जा रहे हैं ; और

(ग) भारतीय व्यापार संवर्धन संस्थान में अनुसूचित जनजाति के लिये विशेष अभियान के अंतर्गत अप्रैल, 1993 में चतुर्थ श्रेणी के पदों को भरने के लिये रोजगार कार्यालय से मांगे गये नामों का परिणाम क्या रहा ?

वाणिज्यिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री और वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) हाल ही में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए एक विशेष भर्ती अभियान शुरू किया गया था और इसके परिणामस्वरूप 14 पद भरे गए थे । अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित 27 और पद आज की तारीख में खाली पड़े हैं ।

(ग) भारत व्यापार संवर्धन संगठन ने सूचना दी है कि अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित श्रेणी-IV के पदों को भरने के लिए, अप्रैल, 1993 में रोजगार कार्यालय से कोई नाम नहीं मंगाए गए ।

Substitution of I.P.R.S. with a Duty-Free Imports

3165. SHRI KAMAL MORARKA : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government propose to substitute the international price reimbursement scheme for engineering goods exporters with a duty free imports scheme;

(b) if so, the details of the scheme; and

(c) by when the new scheme is likely to come into operation?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI KAMALUDDIN AHMED): (a) No, Sir.

(b) and (c) Question do not arise.